

ज्ञान तत्व 172,

- (क) लेख, भाजपा की संभावनाओं में आतंकवाद की उपयोगिता।
(ख) गोधरा रेल दुर्घटना को आक्रमण लिखने पर प्रश्न और उत्तर।
(ग) अरूधन्ती राय द्वारा संसद भवन पर आक्रमण पर संदेह पर प्रश्न और उत्तर।
(घ) प्रचार माध्यमों द्वारा झूठ को सच प्रमाणित करने संबंधी मेरे लेख पर प्रश्न और उत्तर।
(च) रवीन्द्र सिंह पत्रकार द्वारा सिंघला जी का आलोचना और उत्तर।
(छ) प्रहलाद गिरी द्वारा शराब मुक्ति पर सुझाव और उत्तर।
(ज) अमर सिंह आर्य द्वारा पांच प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर।
(झ) धर्मशील चतुर्वेदी द्वारा गांधी के आर्थिक चिंतन पर विचार और मेरा उत्तर।
(ट) कृष्ण कुमार सोमानी द्वारा पंचायती व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका और उत्तर।

(क) भाजपा की संभावनाओं में आतंकवाद की उपयोगिता

भारतीय राजनैतिक शासन व्यवस्था में अब न साम्यवाद का कोई भविष्य है न समाजवाद का। पूरी व्यवस्था आर्थिक आधार पर पूँजीवाद की दिशा में एक तरफा जा रही है जिसमें वामपंथी समाजवादी यदा कदा आलोचना से आगे नहीं बढ़ पाते।

पूँजीवादी व्यवस्था को निर्णायक बहुमत के बाद भी उनके बीच आपसी सत्ता संघर्ष उन्हें कांग्रेस और भाजपा के रूप में दो गुटों में बांटकर रखता है। यह सत्ता संघर्ष इन दोनों को अल्प मत में लाकर साम्यवादियों, समाजवादियों तथा कुछ अन्य ढुलमुल दलों के साथ तालमेल के लिये मजबूर करता रहता है। यह तालमेल ही संप्रग और राजग नाम से पूरी राजनीति को दो ध्रुवों में विभाजित करता है जिसमें एक का नेतृत्व कांग्रेस के पास और दूसरे का भाजपा के पास रहता आया है। अन्य सभी दल ढुलमुल शब्द के अनुसार हमेशा ढुलमुल ही रहा करते हैं जो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर कभी भी किसी के भी साथ किसी भी सीमा तक झुककर या अकडकर तालमेल करते रहते हैं। इसी तालमेल की संभावना में ऐसे ढुलमुल दलों के नेता प्रधानमंत्री बनने तक के स्वप्न भी देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा सपना सच भी हो जाने के कारण ऐसी संभावनाओं को जीवित रखता है।

छ माह पूर्व तक कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव के कारण अपनी स्वाभाविक दिशा छोड़कर लडखडाने के लिये मजबूर थी। साम्प्रदायिकता के मामले में निर्लज्ज मुस्लिम तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप सच्चर आयोग भी बनाना पड़ा और राष्ट्रीय संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार जैसी बात भी कहनी पड़ी। आतंकवाद के मामले में भी कांग्रेस बहुत सतर्क कदम उठाने को मजबूर रहती थी। हर दो चार महिने में मुस्लिम आतंकवादी कहीं न कहीं अपना विस्फोट करके बेगुनाहों का खून कर देते थे और सरकार धिसे पिटे बयानों से आगे बढ़ नहीं पाती थी। आर्थिक मसले में भी कांग्रेस परेशान थी। मंहगाई का ऐसा प्रचार हो रहा था कि कोई समस्या न होते हुए भी मंहगाई को समस्या के रूप में स्वीकार करना पड़ता था। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार मय है और कांग्रेस पार्टी के स्थान पर भाजपा मजबूत होकर उभरेगी। क्योंकि उस समय मंहगाई से भी ज्यादा मजबूत मुद्दा मुस्लिम आतंकवाद था और दो तीन महिने में मुस्लिम आतंकवादी ऐसी आतंकवादी घटनाओं का रिन्जुअल करके भाजपा का ग्राफ़ उपर कर दिया करते थे। उस समय तो भाजपा इतनी गदगद थी कि वह कांग्रेस को परेशान करने के लिये वामपंथियों तक से भी हाँ में हाँ मिलाने में लग जाया करती थी।

एकाएक वातावरण बदला। वामपंथियों पर कांग्रेस की निर्भरता खत्म हुई। कांग्रेस पार्टी कुछ संतुलित हुई। आर्थिक मंदी के हल्ले ने मुद्रा स्फीति को आसमान से पटककर जमीन पर ला दिया। मंहगाई का गुब्बारा पिचक गया। किन्तु मुस्लिम आतंकवाद फिर भी एक समस्या बना हुआ था। भाजपा चाहे कुछ करे या न करे परन्तु मुस्लिम आतंकवादी स्वयं ही भाजपा के वोट बढ़ा दिया करते थे। एकाएक कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आतंकवाद के मुद्दे पर यू टर्न लिया। वाटला हाउस घटना को बड़ी सुझ बूझ से उसने लपक लिया। सभी वामपंथी, मानवाधिकारी, मुस्लिम नेता यहाँ तक कि कुछ कांग्रेसी भी दबे छिपे छाती पीटते रह गये किन्तु कांग्रेस ने किसी

की एक न सुनी। अन्त में तो अन्तुले जी तक को नकाब हटाकर मैदान में आना पड़ा किन्तु कांग्रेस अपने स्टैन्ड पर मजबूती से डटी रही। आतंकवाद के मुद्दे पर उसने नक्सलवाद के विरुद्ध भी अपनी रणनीति बदली। उसने भारत की आम जनता को एक नया संदेश देना शुरू किया कि यदि आतंकवाद किसी हद को पार कर जाता है तो कांग्रेस पार्टी अपने दलीय हितों से उपर उठकर भी राष्ट्र हित में निर्णय कर सकती है। स्वाभाविक ही था कि चुनावों के पूर्व आतंकवाद चुनाव का मुद्दा न बने इसी में कांग्रेस का दलीय हित था और कांग्रेस पार्टी ने इसका भरपूर लाभ उठाया। ऐसे ही कठिन वातावरण में प्रज्ञा पुरोहित प्रकरण सामने आ गया। भाजपा के सामने दुविधा पैदा हो गई। उसने तत्काल आतंकवाद के विरुद्ध स्टैन्ड लिया और कहा कि आतंकवाद आतंकवाद ही होता है चाहे वह मुस्लिम हो या हिन्दू या नक्सलवादी। किन्तु जल्दी ही उसे आभास हुआ कि प्रज्ञा पुरोहित का विरोध करना उसे और मुश्किल में डाल सकता है तो उसने अपना स्टैन्ड बदल लिया और कहना शुरू किया कि हिन्दू आतंकवादी ही नहीं सकता। भाजपा यह भूल गई कि उसकी यह दलील बिल्कुल ही बचकाना है। यदि यह मान लिया जावे तो भाजपा की नजर में नक्सलवादी या तमिल टाइगर्स या तो हिन्दू नहीं है या आतंकवादी नहीं है। प्रज्ञा पुरोहित आतंकवादी है या नहीं इसका अन्तिम निर्णय तो बाद में आया किन्तु भाजपा का कथन झूठ है इसके लिये तो जाँच की जरूरत नहीं। कुछ नये समाचार तो यहाँ तक आये हैं कि पाकिस्तान की आइ एस आई से संघ परिवार के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की मिलीभगत की प्रज्ञा पुरोहित टीम को जानकारी ऐसे कथन का कारण बनी हो। कुछ भी हो किन्तु भाजपा के लिये यह प्रकरण बहुत नुकसान देह सिद्ध हुआ।

ऐसे कठिन समय में बम्बई की आतंकवादी घटना ने तो भाजपा की कमर ही तोड़ कर रख दी। भारत में चुनाव जीतने के लिये मुस्लिम आतंकवाद एक अच्छा मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चालाकी से मुस्लिम आतंकवाद को एक पाकिस्तानी आतंकवाद में बदल दिया। भाजपा कांग्रेस की इस चालाकी को नहीं समझ सकी और उसने भी इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर हमला करने तक की गंभीर मांग शुरू कर दी। कांग्रेस तो ऐसा चाहती ही थी। परिणाम हुआ कि बरसों से भारत में बनी मुस्लिम आतंकवाद की चर्चा बिल्कुल बन्द हो गई। वैसे भी बाटला हाउस के बाद भारतीय मुसलमान बहुत सतर्क होने से कोई नयी आतंकवादी घटना नहीं हुई है और बम्बई की घटनाओं ने तो और भी सब कुछ अस्पष्ट कर दिया है।

बम्बई का हमला राष्ट्रीय टकराव सिद्ध करने में कांग्रेस का लाभ था और धार्मिक आतंकवाद सिद्ध होने से भाजपा फिर से मुस्लिम आतंकवाद का भूत खड़ा कर सकती थी। मेरे विचार से सच भी यही है कि यह आतंकवादी हमला पाकिस्तानी आतंकवाद न होकर धार्मिक आतंकवाद मात्र ही था। यदि किसी पाकिस्तानी सरकारी मशीनरी ने मदद भी की हो तो उसने धार्मिक जोश में आकर ही ऐसा किया होगा। अब तो यह बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो रही है कि आतंक के बल पर शरिया लागू करना मुस्लिम आतंकवादियों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने में इन आतंकवादियों को दुनिया भर के मुसलमानों की सहानुभूति मिल जाया करती है चाहे ये मुसलमान भारत के हों या पाकिस्तान के या कहीं और के। चूंकि ये आतंकवादी पाकिस्तान को अपनी शरणस्थली के रूप में उपयोग कर रहे हैं इसलिये पाकिस्तान पर इसके विरुद्ध दबाव भी बनना चाहिये। किन्तु इस्लामिक आतंकवाद की दिशा ही बदलकर पाकिस्तानी आतंकवाद की तरफ मोड़ दी जावे यह स्टैन्ड ठीक नहीं था। सब जानते हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की अपेक्षा इस्लामिक कट्टरवाद से ज्यादा प्रभावित होता है। यदि पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष हो जाय तो भारतीय मुसलमानों का बहुमत तालिबान के ही तरफ झुकेगा चाहे पाकिस्तान का बहुमत तालिबान विरोधी ही क्यों न हो। किन्तु भाजपा यह फर्क नहीं कर पायी। कांग्रेस पार्टी ने योजना पूर्वक और भाजपा ने भूल वश ऐसा किया जिसका परिणाम हुआ कि भाजपा के हाथ से मुस्लिम आतंकवाद का बचा खुचा मुद्दा भी निकल गया। कांग्रेस के विरुद्ध मंहगाई का मुद्दा वैसे ही निकल चुका था और आतंकवाद का ऐसे निकल गया। चुनावों में अब इतना समय बाकी नहीं है कि कोई नया मुद्दा उठ सकेगा।

पिछले छ माह का यदि आकलन करें तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह अनुशासित, सुनियोजित तथा गंभीर निर्णय लिये और भाजपा ने तात्कालिक, अनुभव हीन, तथा फूहड़ तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत नेतृत्व प्रणाली को स्वीकार कर लिया चाहे उसके गुण दोष कुछ भी क्यों

न हो। भाजपा आज तक न व्यक्तिगत नेतृत्व स्वीकार कर सकी है न सामूहिक नेतृत्व। भाजपा तो आज तक यह भी नहीं बता पाई कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उसका सलाहकार मात्र है या निर्णायक। ऐसी स्थिति में किसी भी राजनैतिक दल के सामने निर्णय की कठिनाई स्वाभाविक ही है और उसी का परिणाम दिखता है कि भाजपा के सामने अगले चुनावों में सरकार बनाना तो दूर पिछली स्थिति तक पहुँच पाना भी कठिन हो सकता है।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(ख) गोधरा रेल दुर्घटना को आपने पूरी दृढ़ता से आक्रमण लिखा। क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आग अन्दर से न लगकर बाहर से ही लगी?

उत्तर— आग कैसे लगी यह अनुमान का विषय है किन्तु गोधरा स्टेशन से रेल चली। थोड़ी दूर जाते ही मुसलमानों की एक भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये। कुछ दूर जाकर गाड़ी रूकी और रेलवे सुरक्षा बल ने लाठी चार्ज करके भीड़ को हटाया। गाड़ी आगे बढ़ी तो कई डिब्बों से चैन खींची गई और थोड़ी दूर जाकर गाड़ी पुनः रूक गई। भीड़ ने बाहर से हमला किया। दो डिब्बों में आग लगी एक के यात्रियों ने बुझाई और दूसरे के जल गये। चैन खींचने वाले और आग लगाने वाले दूर से आने वाले यात्री थे या पहले लाठी चार्ज के समय चढ़ने वाले आक्रमणकारी यह अनुमान आप लगाइये। मैं आश्वस्त हूँ कि आग का सम्बन्ध आक्रमणकारियों से होना अधिक विश्वसनीय लगता है।

(ग) अरुन्धती राय ने संसद भवन पर आक्रमण पर भारत सरकार नियोजित घटना होने का संदेह व्यक्त किया। उसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने ऐसा कहा? यदि कहा तो इसका कारण क्या हो सकता है? उन्होंने कश्मीर के संबंध में जो मत रखा उसमें आपका क्या मत है?

उत्तर— अरुन्धती राय जी ने जो संदेह व्यक्त किया है वह अफजल गुरु को बचाने में प्रकाशित पुस्तक 13 दिसम्बर दि स्टेज केस आफ द अटैफ आन इंडियन पार्लियामेंट में प्रकाशित उनके लेख में पूछे गये प्रश्न संख्या पांच और छ में निहित है कि दिसम्बर तेरह के शीघ्र बाद भारत सरकार ने संसद पर हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की घोषणा भी कर दी और बार्डर पर लाखों सैनिक भी भेज दिये। अरुन्धती जी ने संदेह व्यक्त किया कि भारत सरकार ने तेरह दिसम्बर के हमले के पूर्व ही पाकिस्तान पर हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। उनके ये वाक्य सिद्ध करते हैं कि अरुन्धती जी संसद पर हुए हमले को संदेहास्पद बनाने के लिये संदेह की सीमाओं से आगे चली गई थी।

प्रश्न उठता है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी कठिन काम नहीं। अरुन्धती राय एक ऐसा नाम हैं जो मानवाधिकारों के लिये संघर्ष करने वालों में सम्मान से लिया जाता है। किन्तु उनकी एक कमजोरी है कि वे स्वतंत्र न होकर एक विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं। पूँजीवाद विरोधी वामपंथी विचार धारा उन्हें उक गुट विशेष के साथ जोड़ कर रखती है जिस गुट की पहचान ही है अमेरिका विरोध तथा वामपंथी इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन में मानवाधिकार का उपयोग। उन्होंने अन्य मामलों में कई अच्छे काम किये हैं किन्तु वामपंथ इस्लाम और आतंकवाद यदि एक साथ जुड़ जावे तो उसका समर्थन करना इनकी मजबूरी हो जाया करती है। वैसे भी भारत में जिन लोगों को भी अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं और वे भी सामाजिक क्षेत्र में उनके अधिकांश पुरस्कार में एक गुट विशेष की सहायता बहुत काम आती है। ऐसे मददगारों की टीम के साथ कुछ साथ निभाना भी तो मजबूरी है। अरुन्धती जी के कथन में कितना उनका अपना सोच है और कितनी टीम की मजबूरी यह तो बताना संभव नहीं किन्तु अरुन्धती राय अपने वामपंथी इस्लामिक आतंकवादी विचारों के समर्थन में किसी भी सीमा तक हिम्मत करके तर्क की जगह कुतर्क करने के लिये हमेशा उपलब्ध रहती हैं, यह सही है।

उन्होंने कश्मीर के विषय में कहा कि यदि आवश्यक हो तो कश्मीर को स्वतंत्र करके या पाकिस्तान को देकर भी इस विवाद को खत्म कर देना चाहिये। कश्मीर का प्रश्न उलझा हुआ है। इस मुद्दे पर उनके विचार भिन्न होते हुए भी उनकी नीयत पर संदेह व्यक्त नहीं करते।

यदि कश्मीर समस्या पर गंभीरता से सोचें तो दोनों ही विचारों में दम है (1) कश्मीर पर भारत का अधिकार न्याय संगत न होकर विवादास्पद है। स्वतंत्रता के समय कई सौ रियासतों को भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता का विकल्प चुनने की वैधानिक छूट दी गई थी। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर भारत के साथ विलय के पक्ष में न होकर अलग राह खोज रहे थे। जूनागढ़ तो जल्दी ही निपट गया किन्तु हैदराबाद और कश्मीर का मामला इसलिये कुछ जटिल था कि हैदराबाद का शासक मुसलमान और जनता हिन्दू थी जबकि कश्मीर का शासक हिन्दू और जनता मुसलमान थी। हैदराबाद पर भारत ने उपद्रव कराकर फिर आक्रमण कर दिया और जीतकर अपने में मिला लिया तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने कश्मीर में उपद्रव कराकर आक्रमण कर दिया और जीतने की दिशा में बढ़ने लगा। हैदराबाद को तो अवसर ही नहीं मिला कि वह पाकिस्तान से सम्पर्क करे किन्तु कश्मीर के राजा को अवसर मिला और उसने भारत के साथ विलय कर दिया जिसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया। भारत ने इस विलय के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जनमत संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया किन्तु भारत लाख प्रयत्न करने के बाद भी कश्मीरी मुसलमानों का दिल नहीं जीत सका। इसके विपरीत पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों को कट्टरता की दिशा में लगातार बढ़ाता रहा। जिसके परिणाम स्वरूप भारत को जनमत संग्रह से पीछे हटने के बहाने करने पड़े। भारत को कश्मीर को अपने साथ बनाये रखने के लिये कई युद्ध करने पड़े, खर्चों रूपया उन्हें अतिरिक्त सहायता के रूप में खर्च करना पड़ा, पूरी दुनिया में कमजोर तर्क के कारण कई बार शर्मिन्दा भी होना पड़ा किन्तु उसने कश्मीर को अपने साथ बनाये रखने के बदले में सब नुकसान सहा। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर राष्ट्रीय चिन्तन तो कश्मीर को अपने साथ रखने के पक्ष में दिखता है और मानवीय पक्ष कश्मीर पर झुककर भी समझोते के पक्ष में रहता है।

यह तो कश्मीर का सैद्धान्तिक पक्ष है किन्तु इसका व्यावहारिक पक्ष इसके ठीक विपरीत है। कश्मीर का टकराव दो राष्ट्रों के बीच का टकराव न होकर इस्लामिक विस्तारवाद से भारत का टकराव है। कश्मीर तो उक्त टकराव का एक माध्यम मात्र है। पाकिस्तान कश्मीर में संघर्ष नहीं कर रहा। संघर्ष तो कर रहा है विश्व इस्लामिक मूवमेंट जिसमें पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र और कश्मीर सटा हुआ होने से महत्वपूर्ण पार्ट है।

यदि कश्मीर छोड़ दे तो टकराव थोड़ा आगे बढ़कर पंजाब या राजस्थान में खिसक जायगा जो ज्यादा हानिकारक होगा। कश्मीर का टकराव न्याय अन्याय के बीच न होकर न्यायी और अन्यायी के बीच है जिसमें इस्लाम का विस्तारवाद एक खतरनाक पक्ष है और उससे लड़ना हमारी मजबूरी है। इस्लाम को मानने वाले बड़ी संख्या में धर्म के विस्तार के लिये जान देने में संतोष का अनुभव करते हैं क्योंकि धर्म विस्तार के लिये प्राण देने पर उन्हें धार्मिक लाभ के साथ साथ जन्नत में कुछ ऐसी भौतिक वस्तुएँ भी मिलने का आश्वासन है जो उनके लिये दुहरा आकर्षण का काम करती है। इसके ठीक विपरीत हिन्दू धार्मिक विस्तार से नफरत करता है। वह धर्म रक्षा के लिये तो कभी जान भी दे दे किन्तु विस्तार तो उसने सीखा ही नहीं। इस्लाम यह जानता है कि दुनिया में कोई संस्कृति ऐसी नहीं जो किसी न किसी बहाने अनन्तकाल तक लड़ सके। बहुत वर्षों के बाद कहीं न कहीं हार थक कर समझौता उनका स्वभाव है। यही एक विश्वास है कि इस्लाम हमेशा संघर्ष को हर मोर्चे पर जिन्दा रखता है चाहे वह संघर्ष न्याय संगत हो या अन्याय पूर्ण। अफगानिस्तान, इराक, इजराइल, रूस, कश्मीर चारों ओर तो उसने अनन्तकाल तक का संघर्ष छेड़ रखा है। ऐसे घोषित शत्रु को कश्मीर सौंपना हमारी भारी भूल मान ली जायगी। इसलिये भारत को चाहिये कि वह किसी भी स्तर से इस्लाम का यह धमंड चूर कर दे कि संघर्ष को लम्बा खींचकर वह जीत सकता है। इसके विपरीत उसे यह समझ में आना चाहिये कि ताकत से परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की आदत की पोल खुल चुकी है।

मैं स्वयं पहले वैसा ही सोचता था जैसा अरुन्धती जी कश्मीर के विषय में सोचती हैं। धीरे धीरे मेरी धारणा बदली और उनकी नहीं बदली। इसका कारण भी मैं समझता हूँ कि मैं न तो किसी विचार धारा से प्रतिबद्ध हूँ न किसी गिरोह से धिरा हुआ हूँ किन्तु अरुन्धती जी के सामने भिन्न परिस्थिति होने से उनकी कठिनाई हमें समझनी चाहिये। वे स्वतंत्र भी नहीं हैं और तटस्थ भी नहीं हैं। वे विचारक भी नहीं हैं। वे हैं सामाजिक समस्याओं पर संघर्ष करने वाले एक समूह की सदस्य। उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। इन सबके आधार पर ही हम उनके कार्यों की समीक्षा करें।

(घ) आपने झूठ के पांव लेख में लिखा है कि प्रचार माध्यम झूठ को सच और सच को झूठ प्रमाणित करने में सफल है। क्या यह संभव है? क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिनके आधार पर भारत में यह बात सही कही जा सके? ऐसे प्रयत्नों का समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है?

उत्तर— जब व्यक्ति में बुद्धि और भावना का संतुलन गड़बड़ हो कर किसी एक दिशा में बढ़ने लगता है तब समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति समूह संचालक और भावना प्रधान संचालित की दिशा में बढ़ते जाते हैं। बुद्धि प्रधान लोग प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हैं और भावना प्रधान ऐसे प्रचार से प्रभावित होते रहते हैं। जब बुद्धि प्रधान लोगों में स्वार्थी तत्व अधिक हो जाते हैं तब ये लोग प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर समाज में असत्य को सत्य और सत्य को असत्य के समान स्थापित कर देते हैं। इस तरह जब एक बार असत्य सत्य के समान स्थापित हो जाता है तब वह समाज में एक परिभाषा का रूप ग्रहण कर लेता है और उसे चुनौती देना बहुत कठिन हो जाता है।

सबसे चिन्ता की बात तब शुरू होती है जब निष्कर्ष निकालने में विचार मंथन का महत्व कम होकर प्रचार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जावे। वर्तमान समय में विचार मंथन की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है और प्रचार द्वारा ही विचार बन रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं और कार्यान्वित कर रहे हैं। ऐसे असत्य निष्कर्ष एक दो न होकर इनकी संख्या सैकड़ों में है। ऐसे असत्य अभी भी मजबूत ही हो रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनौती देने वाली पहली और एकमात्र इकाई ज्ञानतत्व ही है जिसकी प्रसार संख्या इतनी कम है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं दिखता। फिर भी यह संघर्ष प्रारंभ तो हो ही चुका है।

वैसे तो पग पग पर ऐसे असत्य सत्य के समान स्थापित हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है किन्तु कुछ असत्य तो समाज पर भूत की तरह चिपट गये हैं। एक ऐसा ही असत्य है अपराध की परिभाषा। प्रचार माध्यमों ने समाज में इस असत्य को सत्य के समान स्थापित कर दिया है कि कानून का उल्लंघन ही अपराध है। इससे भिन्न कोई बात लोग समझते ही नहीं क्योंकि इनके संस्कार में ही यह बात डाल दी गई है। विल्कुल साधारण सी बात है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन अपराध, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन गैर कानूनी तथा सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन अनैतिक होता है। यदि यह बात किसी को बताई भी जावे तो प्रचार माध्यमों ने मूल अधिकारों, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकारों की परिभाषा को भी गड़बड़ कर दिया है। इसलिये समझने में भी कठिनाई होती है। इसी तरह पूरे समाज को यह समझा दिया गया है कि कृत्रिम उर्जा का सस्ता होना श्रमजीवियों के लिये लाभदायक है। सच्चाई यह है कि कृत्रिम उर्जा श्रम शोषक है किन्तु श्रमजीवी गरीब ग्रामीण भी कृत्रिम उर्जा के पक्ष में ही आवाज उठाता रहता है। इसी तरह वर्ग संघर्ष को एक आवश्यक हथियार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। हर आदमी किसी न किसी रूप में वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष में अप्रत्यक्ष सहयोग करता रहता है किन्तु वह ऐसे हानिकारक कार्य को भी समाज हितैषी काम ही समझता रहता है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से उसे यह बात समझा दी गई है। ऐसी अनेक बीमारियाँ समाज में दवा में रूप में प्रचलित हैं या की जा रही हैं जिन पर व्यापक चर्चा करनी होगी।

(च) श्री रवीन्द्र सिंह पत्रकार, संवाद सरोवर, गुना, मध्यप्रदेश

प्रश्न—ज्ञान तत्व एक सौ पैंसठ में अजमेर निवासी एम एस सिंगला जी के विचारों को पढ़कर ऐसा लगा जैसे वे दूसरों को ही हिंसा की प्रेरणा देते रहते हैं परन्तु स्वयं हिंसा कभी नहीं करते। वैसे भी हिंसक स्वभाव से ही डरपोक और कायर होता है। वह मजबूत की तो चापलूसी करता है किन्तु कमजोर के सामने दहाड़ने लगता है। जिनके पास तर्क शक्ति का अभाव होता है वे कुछ ज्यादा ही हिंसा की बात करते हैं।

आप जो भी कर रहे हैं वह अच्छा है। आप विचार मंथन द्वारा विद्वानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यदि आप अपनी शक्ति का कुछ भाग शिक्षा और शिक्षकों के विकास के लिये करते तो अधिक अच्छा होता। शिक्षा के सम्बन्ध में आपके विचार समझ में नहीं आते।

उत्तर— सिंगला जी के विषय में आपने क्या निष्कर्ष निकाला यह आपका और सिंगला जी का विषय है। मैं अपने जीवन में कभी कायर नहीं रहा। मैंने जीवन भर अपराधों एवं अपराधियों से मुकाबला

ही किया है किन्तु हिंसा से नहीं अहिंसा से । पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनकी चर्चा यहाँ उचित नहीं ।

आपने शिक्षा और शिक्षकों के विकास की प्राथमिकता के लिये मुझसे कुछ करने की अपेक्षा की है । मुझे शिक्षा का भी अनुभव है और भूख का भी । मुझे शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों पर हो रहे व्यय और प्रोत्साहन का भी अनुभव है । मैं यह मानता हूँ कि यदि शिक्षा और अन्य अनेक विषयों की तुलना करे तो अन्य अनेक कार्यों की अपेक्षा शिक्षा का महत्व ज्यादा है किन्तु शिक्षा और भूख की तुलना करें तो मैं भूख को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ । यदि समाज में तीन वर्ग बनाए जायें 1 धनवान 2 शिक्षित सामान्य 3 श्रमजीवी गरीब । मैं चाहता हूँ कि एक सीमा से अधिक धन वालों की प्रगति को निरूत्साहित करना चाहिये । बीच वाले बुद्धिजीवियों के मामले में तटस्थ रहना चाहिये और गरीबी रेखा से नीचे वाले श्रमजीवियों की सहायता करनी चाहिये । सम्पूर्ण भारत में सब लोग शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की मांग करते रहते हैं जिनमें आप भी बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं किन्तु मैं हमेशा ही शिक्षा की अपेक्षा श्रम के पक्ष में आवाज उठाता रहता हूँ । मैं जानता हूँ कि ऐसी आवाज उठाने वाला मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ । किन्तु मेरी आत्मा कहती है कि श्रमजीवी बुद्धिजीवी और पूँजीपति की तुलना करते समय श्रमजीवी की अपेक्षा बुद्धिजीवी का समर्थन पाप है भले ही पूरी दुनिया ही ऐसा क्यों न करे ।

किन्तु धन की अपेक्षा शिक्षा और शिक्षक को हमने जीवन भर महत्व दिया है । हमारे क्षेत्र में आज तक जो भी विधायक या मंत्री बने वे स्कूल के शिक्षक रहे । कालान्तर में वे दोनों ही मंत्री भी बने । रामानुजगंज में सर्वोच्च सम्मानित पद नगर प्रमुख का है । नगरपालिका अध्यक्ष , एडिशनल कलेक्टर या उच्च पुलिस अधिकारी से भी उँचा । ऐसे सम्मानित पद के लिये हुए मतदान में एक मिडिल स्कूल के गरीब शिक्षक चुने गये । आपको शिक्षक के लिये इससे ज्यादा क्या सम्मान और प्रोत्साहन हम दे सकते हैं । शिक्षा और शिक्षक के लिये हमारे व्यवहार में जो स्थान है वह और दूसरों से अधिक ही है कम नहीं । किन्तु सुविधा के मामले में श्रम ज्यादा उपेक्षित है । हम श्रम का पेट काटकर शिक्षा और शिक्षक का पेट भरने की नीति के पक्ष में नहीं हैं । आशा है कि आप इस विषय को ठीक से समझेंगे ।

(छ) श्री प्रहलाद गिरि, निंगा, आसनसोल, बंगाल

प्रश्न— आप निस्संदेह सूक्ष्म विचारक हैं और स्वामी राम देव जी भी एक नये भारत और विश्व का निर्माण करना चाहते हैं । आपके विचार से वे समाज राष्ट्र व्यवस्था को किस ढंग से करें कि विश्व के लिये भी अनुकरणीय हो और उस आदर्श विश्व व्यवस्था में आपका सरल बोधगम्य सूत्रों में रचित पुनः संशोधित पुस्तक एक आदर्श संविधान बने ।

दूसरा निवेदन है कि मैं प्रयोग के तौर पर ही अपनी निंगा कोलियरी को शराब मुक्त करना चाहता हूँ । यहाँ 30 प्रतिशत मुस्लिम 70 प्रतिशत हिन्दू है , कुल आबादी 40 हजार की है । यहाँ मैं कौन संगठन किस ढंग से बनाऊँ , कौन अभियान छेड़ू कि यहाँ शराब दुकान एव शराबी बंद हो जाये । यहाँ 40 प्रतिशत लोग शराब पीने लगे हैं पीने वालों में हिन्दू अधिक हैं, मुसलमान अल्प । यदि कोई समिति बनाऊँगा तो उसमें भी शराबी को रखना ही पड़ेगा । यदि मैं प्रतिवर्ष शराब न पीने वाले को शराब न पीने के कारण पुरस्कृत करूँ तो कैसा रहेगा । उनका नाम भी हैंड बिल में छपवा कर बांटू या एक नियम बनवाऊँ कि शराब बंद समिति का कोई सदस्य यदि शराब पीये तो दंड लगाया जाय । वो दंड भी कैसा हो । सरकार से भी इस अभियान के लिये मैं कानून में संशोधन का आग्रह करूँ तो कैसे करूँ ? इसकार्य के लिये आपका ही सुझाव सर्वोत्तम रहेगा । आप पत्र द्वारा या ज्ञानतत्व द्वारा भी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं ।

उत्तर— बाबा रामदेव जी एक विख्यात तथा स्थापित सन्त हैं जो मैं नहीं । रामदेव जी ने समाज की समस्याओं का कारण और समाधान अलग खोजा है और मैंने अलग । सच बात यह है कि मेरा समाधान किसी भी अन्य वर्तमान नेता, महापुरुष, सन्त महात्मा से मेल नहीं खाता । रामदेव जी भी उन्हीं में एक हैं । ये लोग समाज को ठीक करना चाहते हैं किन्तु मैं वर्तमान राजनैतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को सारी गडबडी का कारण मानता हूँ समाज को नहीं । ये लोग व्यवस्था में लगे इन एक करोड़ लोगों का ऐसा हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं कि निर्यान्वये करोड़ लोगों को राहत मिले । मेरी समझ यह बनी है कि इन एक करोड़ लोगों की नीयत खराब होने से

ये जान बूझकर ऐसी गडबडी कर रहे हैं। इसलिये मेरे मतानुसार न निन्यान्वे करोड को सुधारने से समस्या का समाधान होगा न एक करोड बिगाडने वाले सुधारने से सुधरेगें। जिनके सुधारने से सब ठीक होना है वे सुधर ही नहीं सकते तथा जिनके सुधर जाने से भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है उस प्रयत्न में भले ही अन्य सब लगे हो परन्तु मैं तो नहीं लग सकता। मेरे विचार में एक करोड और निन्यान्वे करोड के बीच बढी हुई दूरी को कम करना ही इसका समाधान है जिसमें मैं पूरी ताकत से लगा हूँ। मैं यदि रामदेव जी को समझाने में शक्ति लगाऊँ तो वे समझने की अपेक्षा समझाने का प्रयत्न शुरू करेंगे जिसमें विचार मंथन कम और प्रभाव का उपयोग अधिक होगा। वे कोई गलत तो कर नहीं रहे। जो भी कर रहे हैं वह अच्छा ही है। यह अलग बात है कि मार्ग और दिशाएँ अलग अलग हैं। रामदेव जी को समझाने में शक्ति लगाने की अपेक्षा आप जैसे समकक्ष यदि समझ गये तो अधिक लाभ होगा और तब वे भी समझ सकते हैं।

आप शराब बन्द करने के लिये जन जागृति करना चाहते हैं। यह एक समाज सेवा का काम तो है किन्तु व्यवस्था परिवर्तन का नहीं। मेरे चिन्तन का विषय समाज सेवा न होकर लोक स्वराज्य है। इसलिये इस संबंध में आप क्या मार्ग पकड़ें इससे मैं अनभिज्ञ हूँ। किन्तु इस संबंध में सरकार से सहायता लेना तो धातक कार्य हो जायगा। ऐसे निवेदन ही तो सरकार को प्रेरित करते हैं कि वह समाज को गुलाम बनाती चली जाये। क्या हमारा इतना भी प्रभाव नहीं कि हम कुछ लोगों को शराब छोड़ने हेतु तैयार कर सकें और यदि इतना भी प्रभाव नहीं तो ऐसे काम की ठेकेदारी लेने की क्या जरूरत है? मेरे विचार से यदि सेवा कार्य में बढ़ने की ही इच्छा हो तो अपनी क्षमता अनुसार ही आगे आइये न कि सरकार को आमंत्रित करने की भूल पर। यदि आप लोक स्वराज्य की दिशा में भी कुछ कर सकें तो एक अच्छा सहयोग संभव है।

(ज) श्री अमर सिंह आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रश्न 1. — ज्ञानतत्व के अंक 167 के पूर्वाध्द में गूढ विचार मंथन किया गया। इसमें प्रस्तुत बिन्दुओं पर सारे कार्यक्रम का आधार व विश्व समस्याओं का समाधान निहित है। जो विचार आप दे रहे हैं वे समाज में कितने ग्राह्य हैं और देश का प्रबुद्ध व आम जन इन्हे समझ पा रहा है या नहीं इसका 40 सालों में कभी आंकलन की बात आयी क्या?

प्रश्न 2 — संविधान में परिवार, गांव शामिल नहीं। परिवार, गांव, वार्ड को कमजोर करने का सरकार का हमेशा प्रयास रहता है।

प्रश्न 3 — समाज को तोड़ कर आठ आधारों पर वर्ग निर्माण कर वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष की भूमि तैयार करना राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता है यह 60 वर्षों के अनुभव से सिद्ध है। पर क्या समाज भी ऐसा मानता है? इसका कोई अध्ययन कराया गया है या नहीं।

प्रश्न 4— वर्तमान विधान से इतर भी कोई व्यवस्था हो सकती है, विकल्प हो सकता है इस पर कोई एकमत विचार सामने नहीं आ सका। संविधान पर भिन्न मत तो आते रहे हैं परन्तु संविधान बदलने की बात पर कभी देश विरोधी होने, ताना शाह सम्प्रदायवादी देश को तोड़ने की शक्तियों के सिर उठाने, वर्ग विशेष विरोधी होने आदि के विशेषण दिये जाते रहे हैं परन्तु संविधान पर कभी खुली बहस नहीं हुई जिसमें आम नागरिक शामिल रहे हो। सरकार बहस में आम लोगों को शामिल करने में धबराती है मेरा ऐसा मानना है। ऐसा क्यों? इन बिन्दुओं पर कुछ राजनेताओं बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्री इनसे भिन्न भी मैंने कुछ नौकरी पेशा, छोटे व्यापारी, अध्यापकों, समाज सेवकों, सर्वोदयी कार्यकर्ताओं, अन्य संगठनों से जुड़े लोगों प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की तो पता लगा कि बहुत कम लोग मेरी बताई बातों से सहमत हो पायें। अधिकांश के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ तो सरकार को ही ग्राम राज्य, स्वराज्य मानते हैं। बहुत कम लोग स्वराज्य को सही रूप में समझ पा रहे हैं। राज्य पर समाज के नियन्त्रण की बात पर कितने सहमत हैं? आपका आंकलन स्पष्ट करावें

प्रश्न 5 — धर्म और विज्ञान पर गहन मंथन हुआ, मैं कुछ भिन्न मत रखता हूँ आपने विज्ञान का आधार तर्क और अनुसंधान माना जब कि धर्म का आधार श्रद्धा और विश्वास। मेरे विचार में विज्ञान तर्क अथवा सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधान तो वह प्रक्रिया है जिस पर सिद्धांत व तर्क को परखा जाता है और शोध के परिणामों को सही या गलत ठहराया जाता है।

धर्म की कसौटी भी तर्क व अनुभूति है परन्तु धर्म को भावना का विषय बता कर शोध प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाती है। धर्म क्या है इस पर कभी बहस ही नहीं होती जबकि यह जरूरी है। धर्म भावना का नहीं आचरण का विषय है, भावना से जोड़ कर ही धर्म को विकृति की ओर धकेल दिया गया। धर्म तर्क का विषय नहीं जैसी श्रद्धा वैसा माने यहा से ही मत और पाखण्ड का जन्म होता है चुंकि सत्य जैसा है वैसा मानने के सिद्धांत पर मंथन होना चाहिए उस पर ताला नहीं लगाना चाहिए।

धर्म से सत्य को जाना जाता है और विज्ञान से विभिन्न पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जब विज्ञान का शोध व धर्म का अन्वेषण सही दिशा में बढ़ता है तो पूरक रहते हैं और जब दिशा बदल जाती है तो एक दूसरे की दूरी बढ़ जाती है। यही धर्म और विज्ञान की त्रासदी है। दोनों गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। उसकी ओर स्पष्ट व्याख्या कराकर अनुग्रहित करें।

उत्तर—1. उन्नीस सौ चौरासी तक मैंने राज्य व्यवस्था के माध्यम से समाज की समस्याओं के समाधान के प्रयत्न किये। असफल होने पर पंद्रह वर्षों तक जंगल में बैठकर अनुसंधान किया। नवंबर निन्यानवे तक निष्कर्ष निकला कि भारतीय संविधान ने लोकतंत्र की परिभाषा ही चुपचाप बदल दी है। चार नवंबर निन्यानवे के बाद पांच वर्षों तक मैंने रामानुजगंज नगर पंचायत में लोक स्वराज्य का प्रयोग किया। दो हजार पांच से आठ तक के चार वर्षों तक दिल्ली में रहकर अन्तिम निष्कर्ष पर विचार किया और पच्चीस दिसम्बर आठ को दो दिशाओं में सक्रियता का अन्तिम निष्कर्ष निकला 1 मानसिक व्यायाम 2. लोक स्वराज्य आंदोलन। पचीस दिसम्बर तक तो निष्कर्ष ही अन्तिम नहीं था। अब निष्कर्ष अन्तिम रूप से निकला है। अब आगे पता चलेगा कि यह विचार कितना ग्राह्य है कितना अग्राह्य।

2. सरकार हमेशा ही परिवार, गांव समाज को कमजोर करने का प्रयास करती है आपके इस निष्कर्ष से मेरी पूरी सहमति है।

3. राज्य और राज्य से जुड़े लोग परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से धर्म जाति भाषा आदि आठ वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष के उपायों का उपयोग करते हैं यह सच्चाई समाज अब तक नहीं समझ पाया है। यह बात समाज को समझाने की आवश्यकता है।

4. सरकार से जुड़े लोग संविधान पर खुली बहस से इसलिये कतराते हैं कि वर्तमान संविधान में ही उनकी सुरक्षा है। यदि संविधान के दोष स्पष्ट हो जायें तो राज्य से जुड़े लोगों की पोल खुल जावेगी। समाज में संविधान चर्चा अब तक नगण्य है किन्तु धीरे धीरे बढ़ रही है। रामबहादुर राय जी तो इस संबंध में प्रतिमाह एक गोष्ठी करते रहते हैं। काम कठिन है किन्तु कोई अन्य मार्ग नहीं है।

5. धर्म के दो अर्थ मैंने पिछले अंक में बताये हैं 1 गुण प्रधान 2 संगठन प्रधान। यदि पहले अर्थ की चर्चा करे तो विज्ञान संबंधी आपकी व्याख्या ठीक है और संगठन संबंधी अर्थ करे तो मेरी व्याख्या ठीक है।

पचीस दिसम्बर को मैंने समाधान आप सबको बता दिया है आप आगे काम शुरू करिये। मेरा जहाँ सहयोग चाहिये मैं आपके साथ हूँ।

5. डा. महावीर सिंह अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल बरेली

विचार— अहिंसक क्रांति के अग्रदूत महात्मा गांधी अब और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। नागपुर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषित किया गया कि गांधी का विकास मॉडल ही सर्वश्रेष्ठ है।

गांधी जी के विकास मॉडल के केन्द्र में व्यक्ति और नैतिकता है। गांधी जी विकास का अभिप्राय सच्ची सम्यता मानते थे। वे कहते थे " सम्यता वह आचरण है जिससे मनुष्य अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने का मतलब है नीति का पालन करना नीति के पालन का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को वश में करना।"

बापू आवश्यकताओं को सीमित रखने को सुख का आधार मानते थे। वे अमर्यादित तृष्णा वृद्धि को विकास नहीं वरन विनाश मानते थे। बापू कहते थे " धरती माँ में समस्त प्राणियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता है, परन्तु वह एक व्यक्ति की भी तृष्णा को शांत नहीं कर सकती। "

गांधी जी ने ऐसा विकास माडल विकसित किया था जिससे सब को रोजगार मिले जिससे लोग अपनी भोजन वस्त्र मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता पूर्ति में स्वावलंबी हों। जिससे अमीर गरीब का अंतर न बढ़े जिसमें पर्यावरण का क्षरण न हो, जिसमें परस्पर प्रेम और नैतिकता में वृद्धि हो तथा लोग निरोगी और संतुष्ट हो। इन सब महत्वपूर्ण आशाओं की पूर्ति कृषि कुटीर उद्योग वाली शरीर श्रम प्रधान अल्प पूँजी वाली विकेंद्रित अर्थ व्यवस्था से ही हो सकती है। यही गांधी जी का सर्वश्रेष्ठ विकास माडल था। गांधी जी के अनुयायी विद्वान शूमाखर कहते हैं “ लघु ही सुंदर है ”

अब देखना है कि संघ परिवार पूँजीवाद से गांधी मार्ग की ओर कब बढ़ेगा ?

(झ) श्री धर्मशील चतुर्वेदी उत्तर बेनिया नाग, वाराणसी 221001

प्रश्न— ज्ञान तत्व मिलता है। मैं राष्ट्रीय पुनरोत्थान के आपके विराट यज्ञ के प्रति समर्पित हूँ। आपके माध्यम से विचारको के लिए एक प्रश्न रखना चाहता हूँ—

मार्क्सवाद अपने आर्थिक दर्शन में असफल रहा, पूँजीवाद की असफलता या कहे खोखलापन इस विश्वव्यापी मन्दी के रूप में सामने है। अब तो लगता है गांधी का आर्थिक चिन्तन ही एकमेव सर्वथा सुरक्षित अर्थनीति है जिस पर गहन चिन्तन होना चाहिए।

सुरक्षा पेंशन संबंधी आचार्य पंकज के विचार गम्भीर मनन के लिए बाध्य करते हैं इसलिये तत्काल कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।

उत्तर — मैं चतुर्वेदी जी के विचार से सहमत हूँ कि असफल सिद्ध मार्क्सवादी अर्थ व्यवस्था तथा असफलता की ओर अग्रसर पूँजीवाद के विकल्प के रूप में गांधीवादी अर्थ व्यवस्था पर विचार मंथन होना चाहिये किन्तु मैं गांधीवादी अर्थ व्यवस्था को केन्द्र में रखकर कोई संघर्ष, कार्यक्रम या योजना पर सक्रियता के विरुद्ध हूँ। मेरे विचार में गांधी के बाद का सर्वोदय यहीं सक्रियता की भूल कर रहा है। गांधी जी राजनैतिक आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर संतुलित चिन्तन तथा सक्रियता में निपुण थे। राजनीतिज्ञ पूरा जोर देता है कि समाज आर्थिक सामाजिक धार्मिक विषयों पर तो चिन्तन भी करे तथा सक्रिय भी रहे किन्तु राजनैतिक संवैधानिक विषयों पर ज्यादा माथापच्ची न करके वह राजनेताओं के लिये छोड़ दे। राजनीतिज्ञ पूरा जोर देता है कि समाज आर्थिक सामाजिक धार्मिक विषयों पर तो अधिक से अधिक आन्दोलन करे किन्तु राजनैतिक विषयों पर आन्दोलित न हो। दुर्भाग्य से हमारे सर्वोदयी मित्र उनके जाल में फँसकर गांधी के राजनैतिक सोच पर तो खानापूर्ति करते हैं किन्तु सामाजिक आर्थिक विषयों पर खूब चर्चा भी करते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। गांधी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है राजनैतिक आजादी। शेष आर्थिक सामाजिक धार्मिक आजादी उसके बाद है। गांधी के बाद जय प्रकाश के आंशिक प्रयत्न को छोड़कर कभी सर्वोदय ने राजनैतिक आजादी को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी। गांधी जी के विकास माडल का पहला सूत्र था “ राज्य की गुलामी से अधिकतम स्वतंत्रता का संघर्ष ”। इस संघर्ष के लिये नैतिकता और चरित्र को आधार बनाना चाहिये। हमारे गांधीवादी मित्र राज्य और राजनीति से निरपेक्षता की बात करते हैं जबकि गांधी जी ने स्वतंत्रता की बात की थी। बल्कि उन्होंने तो राजनीति निरपेक्षता का विरोध तक किया था। अब यदि हम उनको मानने वाले लोग स्वतंत्रता और निरपेक्षता का अन्तर ही न समझें तो यह हमारा दोष है, गांधी का नहीं। जब तक हम राजनैतिक गुलामी से मुक्त नहीं हो जाते तब तक चरित्र और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर सक्रियता या आंदोलन हमारी कायरता की राह है। आज राज्य लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। समाज और व्यक्ति की राज्य पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध गांधीवादी ठाकुर दास बंग ने चरित्र और नैतिकता को आधार बनाकर लोक स्वराज्य के लिये सर्वोच्च सक्रियता की योजना प्रस्तुत की है। ऐसे समय में बंग जी की लोक स्वराज्य योजना के विरोधी गांधीवादी सर्वोदयी नैतिकता, चरित्र, स्वदेशी जैसे आर्थिक सामाजिक, धार्मिक मुद्दों को आगे उछालकर राज्य की ढाल बनें और बंग जी की लोक स्वराज्य योजना का किसी न किसी बहाने से विरोध करें तो ऐसे गांधी का नाम उपयोग करके समाज में भ्रम फैलाने वालों को हम क्या कहें? गांधी जी ने तो संघर्ष की एक स्पष्ट राह बताई है। अब यदि कोई राही राज्य से संघर्ष की राह छोड़कर अपनों से ही संघर्ष की राह दिखाना शुरू कर दे तो ऐसे व्यक्ति को हम राही माने या राह विरोधी यह समझने की आवश्यकता है।

आप दोनो ने गांधी जी की आर्थिक नैतिक सोच का जो विवरण दिया है वह राजनैतिक संघर्ष का सहायक होना चाहिये न कि मौलिक। जब मुझे आभास होता है कि गांधी जी के नैतिक सामाजिक आर्थिक विचारों को सुविधा जनक कार्य मानकर प्राथमिकता देनी शुरू कर दी जाती है तब मुझे चिन्ता भी होने लगती है और संदेह भी। जब तक बंग जी दुर्गा प्रसाद जी, खन्ना जी, त्यागी जी अमरनाथ भाई आदि की टीम ने पहल नहीं की थी तब तक तो मुझे पहल का अभाव दिखता था किन्तु अब पहल के बाद भी कोई इस योजना का विरोध करे तो उसकी नीयत मे ही खोट है ऐसा माना जाना चाहिये।

आपने जो व्याख्या की है उससे मैं सहमत हूँ। किन्तु सभी राजनैतिक दलों का समान उद्देश्य है " गांधी के नाम पर समाज को राजनैतिक विचार मंथन की राह से भटकाकर नैतिकता चरित्र आर्थिक सामाजिक विषयों पर विचार मंथन या संघर्ष की राह में सक्रिय करना"। इस प्रयत्न से राज्य निष्कण्टक होता है। ऐसे प्रयत्न में कांग्रेस साठ वर्षों तक समाज को धोखा देती रही है और भाजपा ने भी अब गांधी के नाम की उपयोगिता समझ ली है। भाजपा की कभी कोई स्वतंत्र आर्थिक सोच नहीं है। भाजपा देश काल परिस्थिति अनुसार पूँजीवाद, समाजवाद, गांधीवाद के आर्थिक चिन्तन को समय समय पर अल्प काल के लिये उधार लेती रही है। हम लोग ऐसे राजनैतिक दलों के आर्थिक रंग बदलते बयानों से सतर्क रहें तो अच्छा है।

आर्थिक मामलों में मौलिक सोच तीन है 1. पूँजीवाद जो सम्पत्ति की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार करके सम्पत्ति व्यक्तिगत मानता है 2. साम्यवाद जो सम्पत्ति को पूरी तरह राज्य की मानकर उस पर किसी तरह का व्यक्तिगत अधिकार मानता ही नहीं। 3. गांधीवादी जो सम्पत्ति को समाज की मानकर व्यक्ति को उसका ट्रस्टी स्वीकार करता है। इन तीनों में गांधीवाद का परीक्षण आज तक नहीं हुआ। गांधीजी के ट्रस्टी शिप के सिद्धांत की कोई सरल व्याख्या का भी अभाव रहा है। यदि वे जीवित रहे होते तो संभव है कि कुछ और साफ समझ में आता। किन्तु उसका अब कोई हल नहीं। मैंने अपने चिन्तन तथा देश काल परिस्थिति के अनुभव के आधार पर एक चौथा निष्कर्ष निकाला है। जिसके अनुसार सम्पत्ति न व्यक्ति की होगी न राज्य की। होगी वह समाज की। समाज व्यवस्था की पहली मान्य इकाई परिवार है और उसके बाद गांव। मेरे विचार में व्यक्तिगत सम्पत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर उसे इस प्रकार व्यक्तिगत किया जाये कि व्यक्ति का परिवार छोड़ते समय ही उसका व्यक्तिगत अधिकार हो। शेष समय में न उसका अधिकार हो न स्वामित्व। इस विषय पर संकेत ही पर्याप्त है। अधिक विवेचना अलग प्रश्नोत्तर से की जा सकती है। इस तरह आर्थिक मामलों में मौलिक विचार मंथन करने की आवश्यकता है। जिसमें गांधी जी की सोच भी मौलिक स्थान रखती है।

(ट) प्रश्न – श्री कृष्ण कुमार जी सोमानी, बम्बई

ज्ञान तत्व एक सौ उन्हत्तर में आपने मेरे पत्र का उत्तर दिया। लगता है कि आपसे कही भूल हुई है। मैं भी मानता हूँ कि व्यक्ति को सुधारने की अपेक्षा व्यवस्था को सुधारना अधिक परिणाम दायक होता है। अनेक इमानदार राजनेता भी पार्टी फड के लिये अपने साथियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार पर आंख फेरते रहे हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिये ही मैं पंचायती राज का पक्षधर हूँ। किन्तु मेरे विचार में यदि चुनाव प्रणाली को ठीक ठाक किये बिना ही पंचायती राज आ गया तो पंचायतो में भी भ्रष्ट लोग बैठ जावेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे।

आपने राष्ट्रपति के वेतन वृद्धि को आधार बनाया वह ठीक नहीं। पचास वर्षों में न्यायाधीशों के वेतन नहीं बढ़ने के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़ा। वैसा ही सब जगह संभव है।

आपने मेरे विषय में निष्कर्ष निकाला है कि मैं राजनेताओं के पक्ष में हूँ। सच्चाई यह है कि मैं पूरी तरह उनके विरुद्ध हूँ।

फिर भी मैं आप द्वारा प्रतिपादित अहिंसा की अवधारणा से सहमत नहीं। यदि कोई समझाने बुझाने से न माने तो उसे ताकत से मनाना एक उचित समाधान है भी और माना भी जाता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। इसी तरह मैं राष्ट्र से समाज को बड़ा मानने की धारणा से भी सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि अब तक कोई विश्व व्यवस्था बन ही नहीं पाई है तो राष्ट्र से उपर किसी सरकार या व्यवस्था का आधार ही संभव नहीं।

उत्तर— पंचायती राज दो प्रकार का है 1 लोकतंत्र मे पंचायती राज 2 लोक स्वराज्य मे पंचायती राज । लोकतंत्र मे पंचायती राज्य व्यवस्था मे पंचायतो को अधिकार तथा दायित्व राज्य द्वारा दिये जाते है तथा उन पर अनुशासन राज्य का होता है, नागरिको का नही। लोकस्वराज्य के पंचायती राज्य मे पंचायतो का अधिकार तथा दायित्व नागरिको द्वारा दिये जाते है तथा अनुशासन भी सरकार का न होकर नागरिको का ही होता है । लोक तांत्रिक प्रणाली मे चुनाव प्रणाली का सीमित महत्व ही होता है निर्णायक नही। मै लोक स्वराज्य प्रणाली वाले पंचायती राज्य की चर्चा कर रहा हूँ।

लोकतांत्रिक पंचायती राज मे भ्रष्टाचार बढ सकता है किन्तु बढने घटने की बात ठीक से समझनी होगी। वर्तमान केन्द्रित व्यवस्था मे यदि सौ लोग मिलकर सौ करोड का भ्रष्टाचार करते है तो प्रति व्यक्ति एक करोड रूपया हुआ। पंचायती राज व्यवस्था मे केन्द्रित व्यवस्था की अपेक्षा सौ गुना अधिक लोगो की भूमिका होगी। हो सकता है कि ये दस हजार लोग मिलकर दो सौ करोड का भ्रष्टाचार कर लें। समझना होगा कि भ्रष्टाचार घटा या बढा। अधिकार और दायित्व जितने ही कम होंगे उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा। मेरे विचार मे केन्द्रित भ्रष्टाचार की अपेक्षा विकेन्द्रित भ्रष्टाचार कम घातक है। इसलिये मै जब तक लोक स्वराज्य व्यवस्था नही आती तब तक के लिये भी पंचायती राज का ही पक्षधर हूँ।

आपका मानना है कि न्यायाधीशो के वेतन पचास वर्षो मे नही बढे। यह बात सही नही है। उनके वेतन भत्ते भी समय समय पर पुनरीक्षित होते रहे है । मै समझता हूँ कि यदि न्यायाधीशो के वेतन भत्तो का न बढना भ्रष्टाचार बढने का कारण है तो जिनके भत्ते खूब बढे उनमे और अधिक भ्रष्टाचार बढने का कारण क्या है ? आपका मानना है कि भ्रष्टाचार राजनेताओ की मजबूरी है। यदि एक सर्वे किया जाय कि यदि चुनाव खर्च न हो तो कितने प्रतिशत राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार नही करेगें तो ऐसा प्रतिशत बहुत कम ही होगा। भ्रष्टाचार प्रवृति है जो अधिकार पाकर तेजी से बढती है और अधिकार कम होने से छटपटाकर सूख जाती है । भ्रष्टाचार को किसी मजबूरी से जोडना ठीक नही।

मेरा मन यह है कि किसी अपराधी को दण्ड देने के लिये किसी व्यवस्था की आवश्यकता है । समाज को सीधा दण्ड देने की सलाह के मै विरुद्ध हूँ। आप भी जीवन मे कभी सीधा दण्ड दिये नही है किन्तु दूसरो को हिंसा के लिये प्रोत्साहित करते रहते है जो मै नही करता। दण्ड देना व्यवस्था का काम है । यदि व्यवस्था वैसा नही करती तो व्यवस्था को बदला जाय नकि अव्यवस्था का समर्थन किया जाय। अभी व्यवस्था को बदलना संभव है इसलिये मै अराजकता के विरुद्ध हूँ। सिंगला जी अजमेर वाले भी आपके ही मत के है । वे भी हिंसा नही करते किन्तु दूसरो को हिंसा के लिये प्रोत्साहित करते रहते है । मै उससे सहमत नही रहा ।

राष्ट्र और समाज के विषय मे भी सोचने की जरूरत है। मेरे विचार मे समाज की भिन्न भिन्न इकाइयो मे व्यक्ति परिवार गांव जिला प्रदेश और राष्ट्र शामिल होते है। विचारणीय प्रश्न यह है कि राष्ट्र अपनी अपनी अन्य इकाइयों का पूरक है या मालिक । यदि व्यक्ति परिवार गांव आदि के आन्तरिक मामलो मे राष्ट्र या राज्य को निर्णायक अधिकार प्राप्त है तो मै इसके विरुद्ध हूँ। राष्ट्र स्वयं समाज व्यवस्था का एक घटक है न कि मालिक। परिवार गांव जिले राष्ट्र से । समाज का अर्थ सिर्फ विश्व व्यवस्था ही नही है। समाज का अर्थ है व्यक्ति ,परिवार , गाव ,जिला प्रदेश राष्ट्र आदि का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी और मिला हुआ अस्तित्व भी । राष्ट्र को बडा मान लेने से समाज के अन्य घटको के स्वतंत्र अस्तित्व की भावना कमजोर हो जाती है । साथ ही इससे विश्व व्यवस्था के मार्ग मे भी बाधा आती है इसलिये मैने यह विचार दिया है ।

